जब उन्हें पदोन्नत किया गया था तब आयोग के नाम प्राप्त नहीं किए गए थे और न ही उनके नाम 'G' सूची में लाए गए थे, लेकिन उनकी पदोन्नति के बाद 1989 बैच के पदोन्नत व्यक्ति तब तक निर्बाध रूप से पद पर बने रहे जब तक कि आयोग द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित नहीं कर दिया गया जब आयोग ने उनके नामों को पदोन्नति की तारीखों से 'G' सूची में लाने की मंजूरी दे दी। इसलिए वे अपनी अस्थायी सेवा के लाभ के हकदार हैं जो उन्होंने डी. एस. पी. के रूप में प्रदान की थी और उस सेवा को उनकी वरिष्ठता के लिए गिना जाना चाहिए। हमने याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत निर्णयों को ध्यान से देखा है और पाया है कि वे तथ्यों पर अलग हैं और याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं।

(11) समापन से पहले, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि रिट याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में यह भी अनुरोध किया था कि वह उस तारीख से सेवा में पुष्टि के हकदार थे जब आयोग ने डीएसपी के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी और प्रतिवादीगण ने उन्हें वह लाभ नहीं देने में गलती की थी, लेकिन इस याचिका पर बहस के समय दबाव नहीं डाला गया था।

(12) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

(13) नतीजतन, रिट याचिका विफल हो जाती है और उसे लागत के किसी आदेश के बिना के खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन. के. सूद के समक्ष, जे. जे.

रविंदर कौर-याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ आवास बोर्ड और अन्य-उत्तरदाता

C.W.P. No 8787 OF 2000

9 मई, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-*चंडीगढ़ आवास बोर्ड (आवंटन, प्रबंधन और मकानों की बिक्री) विनियम, 1979-विनियमन 17-गलत बयान* देकर *दो फ्लैटों का आवंटन-कारण बताओ नोटिस के जवाबों पर विचार करने के बाद आवंटन रद्द करना-आवंटन रद्द करने से पहले कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई-क्या यह* नियम 17 *का उल्लंघन करता है- अभिनिर्णीत,नहीं-Reg. 17 आवंटी को मौखिक सुनवाई देने की परिकल्पना नहीं करता है।*

अभिनिर्धारित किया कि विनियम 17 प्रत्येक मामले में मौखिक सुनवाई की परिकल्पना नहीं करता है। यह केवल आबंटित व्यक्ति के प्रतिकूल किसी भी आदेश को पारित करने से पहले एक उचित अवसर के अनुदान को स्वीकार करता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ मौजूद सारे साक्ष्य का खुलासा उन्हें कर दिया गया था। उन्हें समझाने का मौका दिया गया। उन्होंने अपना लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया था। इन पर विधिवत विचार किया गया था। इस प्रकार, विनियमन 17 में निहित प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

(पैरा 13)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत सुनवाई एक आवश्यक आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष खेल के नियमों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ये न्याय को बढ़ावा देने के लिए हैं। प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। याचिकाकर्ता न केवल आवास बोर्ड को धोखा देने और गलत जानकारी देने की कोशिश करने के दोषी हैं, बल्कि उन्होंने प्रतिवादी-हरजित सिंह को गुमराह करके काफी पैसा भी कमाया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को कोई भी राहत देना बेईमानी को बढ़ौता के बराबर होगा। हम ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए खुद को राजी नहीं कर सकते। वास्तव में, अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का उपयोग अन्याय को पूर्ववत करने के लिए किया जाना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। बेईमान और लालची को पुरस्कृत करने के लिए नहीं।

(पैरा 15 &18)

वी. के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता

जे. एल. मल्होत्रा, *अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से*

ए. के. मित्तल, *अधिवक्ता-प्रतिवादी न. 1 और 2 के लिए,*

संजय सिंहमार, अधिवक्ता-प्रतिवादी *न. 3 के लिए।*

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, जे (मौखिक)

(1) ये दो याचिकाएं एक सामान्य प्रश्न को उठती हैं -फ्लैट न. 3898 और 3898/1, सेक्टर 47-डी, चंडीगढ़ के आवंटन को रद्द करने की प्रतिवादी-बोर्ड की कारवाई, 11 अप्रैल, *2000* के आदेशों के तहत, निरस्त है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रस्तुत नहीं किया गया था?

(2) कुछ तथ्य जिन पर कोई विवाद नहीं है, उन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(3) याचिकाकर्ता पति-पत्नी हैं। जून, 1976 में याचिकाकर्ताओं ने चंडीगढ़ आवास बोर्ड को फ्लैटों के आवंटन के लिए दो आवेदन प्रस्तुत किए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि एक इकाई में भूतल और ऊपरी मंजिलों पर फ्लैट आवंटित किए जाएँ। लॉट के ड्रॉ के बाद, याचिकाकर्ताओं से हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया कि उन्होंने या उनके रिश्तेदारों ने चंडीगढ़, मोहाली या पंचकूला में आवासीय फ्लैट या घर के आवंटन के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है। 11 फरवरी, 1980 को दोनों याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ हलफनामा दायर किया कि "मैंने या मेरी पत्नी/पति ने आवासीय फ्लैट के लिए आवेदन किया था... और आवास बोर्ड चंडीगढ़ द्वारा आवास इकाई के आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार घर और उक्त *आवासीय फ्लैट/घर को आत्मसमर्पण कर दिया* है।" इन हलफनामों को दाखिल करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 25 फरवरी, 1980 को दोनों फ्लैटों का कब्जा ले लिया था। इसके बाद उन्होंने मासिक किश्तों का भुगतान किया। 8 जून, 1992 को दोनों ने 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' जारी करने के लिए आवेदन दायर किया।

(4) 22 नवंबर, 1994 को याचिकाकर्ताओं को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए गए थे कि आवंटन क्यों रद्द नहीं किया जाए। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आरोप लगाया गया था कि आवेदन जमा करने के समय उन्होंने आवेदन पत्रों में गलत जानकारी दी थी और 11 फरवरी, 1980 के हलफनामों में गलत घोषणाएं की थीं। यह बताया गया कि दोनों याचिकाकर्ताओं की शादी ऐसे ही दूसरे से हुई थी। इसके बावजूद, उन्होंने इस जानकारी को अपने पास रखा और ऐसी जानकारी दी जो उनकी जानकारी में गलत थी। वास्तव में, विभिन्न स्थायी और पत्राचार पते देकर बोर्ड को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास किया गया था।

याचिकाकर्ता रविंदर कौर ने आवेदन पत्र या हलफनामे में अपने पति के नाम का भी खुलासा नहीं किया। उन्होंने वास्तव में अपने पिता के नाम का उल्लेख किया था।

(5) याचिकाकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिसों के लिए अलग-अलग जवाब प्रस्तुत किए। इन पर विचार किया गया और अंत में, विवादित आदेश पारित किए गए। 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 8839 में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पारित आदेश की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक P-5 में है।

(6) याचिकाकर्ताओं ने आरोप *लगाया* है कि आदेश विनियमन 17 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि प्राधिकरण द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पहले उनकी व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की गई थी। इस आधार पर यह प्रार्थना की गई है कि आवंटन को रद्द करने और भुगतान की गई राशि को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए।

(7) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक जवाब दावा दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न चरणों में दिए गए बयानों में विभिन्न त्रुटियों की ओर इशारा किया गया है। यह भी कहा गया है कि श्रीमती. रविंदर कौर ने फ्लैट को एक हरजीत सिंह को बेच दिया है। उन्होंने 19 मई, 1999 को बेचने का समझौता किया था। इसके बाद, उन्होंने खरीदार को एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक वसीयत और 21 जून, 1999 का एक हलफनामा दिया था। 21 जून, 1999 को प्रतिफल राशि की प्राप्ति पर संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा हरजित सिंह को सौंप दिया गया था। यह तथ्य 10 अप्रैल, 2000 को जांच अधिकारी, विशेष अपराध प्रकोष्ठ, सेक्टर 17, चंडीगढ़ से एक पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड के संज्ञान में आया था। उन्होंने बताया था कि हरजीत सिंह की शिकायत पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि श्रीमती. रविंदर कौर ने उससे चंडीगढ़ के सेक्टर 47-डी में मकान संख्या 3898/1 की बिक्री के संबंध में 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी।। प्रतिवादीगण का कहना है कि आदेश नियमों और विनियमों के अनुरूप है। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया था और गलत बयान दिए थे, इसलिए विवादित आदेश पारित किए गए हैं। यह कहा जाता है कि आदेश विनियमन 17 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(8) हरजित सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर, उन्हें याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।

(9) पक्षों के वकील को सुना गया है। भले ही याचिका में विभिन्न आधार उठाए गए हैं, लेकिन सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं की ओर से एकमात्र तर्क यह है कि आदेश विनियमन 17 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

(10) विनियम 17 के प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है। यह नीचे लिखा है:—

> "17. पट्टा रद्द करना:बोर्ड आबंटन की किसी भी शर्त के उल्लंघन के आधार पर किसी विशेष हिस्से/फ्लैट के किसी भी आबंटित व्यक्ति या अवक्रेता के पट्टे को रद्द कर सकता है और बोर्ड को पहले से ही भुगतान किए गए धन का पूरा या हिस्सा जब्त कर सकता है और उसके बाद से संपत्ति बोर्ड में निहित होगी। बशर्ते पट्टा रद्द करने से पहले आबंटित व्यक्ति/अवक्रेता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए।"

(11) विनियमन प्राधिकरण को आवंटन रद्द करने का अधिकार देता है। हालाँकि, पट्टा रद्द करने से पहले आबंटित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विनियमन के संदर्भ में यह नहीं कहा गया है कि आबंटित व्यक्ति को मौखिक सुनवाई दी जानी चाहिए।

(12) वर्तमान मामले में, यह स्वीकार की गई स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न आधारों का संकेत देने वाले कारण बताओ नोटिस दिए गए थे, जिन पर आवंटन के आदेश को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया था। उन्हें जो कुछ भी कहना चाहते थे, कहने का मौका गया था। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने विस्तृत जवाब दाखिल किए थे। अभिलेख पर अनुलग्नक के रूप में प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं ने कुछ और बताना होगा। यह भी ध्यान देने

योग्य है कि कारण बताओ नोटिसों के जवाब में व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं मांगा गया था। यह सुझाव नहीं दिया गया था कि याचिकाकर्ता कोई साक्ष्य पेश करना चाहते थे या वे मौखिक रूप से सुनवाई चाहते थे।

(13) हमारे विचार में, विनियमन 17 प्रत्येक मामले में मौखिक सुनवाई की परिकल्पना नहीं करता है। यह केवल आबंटित व्यक्ति के प्रतिकूल किसी भी आदेश को पारित करने से पहले एक उचित अवसर के अनुदान को स्वीकार करता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मौजूद सारे साक्ष्य का उन्हें खुलासा किया गया था। उन्हें समझाने का मौका दिया गया। उन्होंने अपना लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किया था। इन पर विधिवत विचार किया गया था। हम संतुष्ट हैं कि इस पर विधिवत विचार किया गया था। हम संतुष्ट हैं कि विनियमन 17 में निहित प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

(14) श्री जैन का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार था। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। कारण बताओ नोटिस के जवाब में भी व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर कभी नहीं मांगा गया था। दूसरा, हमें यह निर्धारित करने का कोई आधार नहीं मिला है कि हर *मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की* जानी चाहिए। भारत *संघ और एक अन्य* बनाम जेनेसस सेल्स कॉर्पोरेशन (1) में उनके लॉर्डशिप्स को निम्नलिखित अवधारणा करने में खुशी हुई:—

> "हालाँकि विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता अलग-अलग होती है। अदालतें इस बात पर जोर नहीं दे सकतीं कि सभी परिस्थितियों में और विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत सुनवाई संबंधित व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। यदि व्यक्तिगत सुनवाई के इस सिद्धांत को इतना बढ़ाया जाता है जब भी वैधानिक अधिकारियों को वैधानिक अपीलों के संबंध में विवेकाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति दी जाती है, *तो यह अराजक परिस्थितियों का कारण बन जाएगा। जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किसी भी अपील या आवेदन पर प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले सुनवाई के अवसर की आवश्यकता होती* है, तो इसका मतलब सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत सुनवाई नहीं होता है। (जोर दिया गया)। आवश्यकता का पालन
>
> (1) 1996 (4) एस. सी. सी 69
>
> संबंधित व्यक्ति को ऐसे अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दे के किया जाता है, जिससे अपेक्षित है कि वह अपने न्यायिक दिमाग को शामिल मुद्दों पर लागू करे।"

(15) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रत्येक मामले में एक आवश्यक आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष खेल के नियमों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ये न्याय को बढ़ावा देने के लिए हैं। प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-बोर्ड को धोखा देने के लिए लगातार प्रयास किए थे। विवादित आदेश का अवलोकन उनके आचरण को पूरी तरह से सामने लाता है। यह पाया गया है कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में दी गई कहानी मनगढ़ंत है। उन्होंने इस हद तक अभिवचन किया है कि उनके संबंध तनावपूर्ण थे और वे अलग रह रहे थे। वास्तव में, यह पाया गया है कि उनके द्वारा आवेदन पत्र एक ही हाथ, स्याही और कलम से भरे गए थे। 24 जून, 1976 को उन्हें एक ही शपथ आयुक्त से प्रमाणित किया गया था। इन्हें उसी दिन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सीरियल नंबर 1056 और 1057 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्रों के साथ जमा किए गए बैंक मसौदों को उसी दिन उसी बैंक से खरीदा गया था और उन पर लगातार नंबर लिखे हुए थे। दोनों ने अपना स्थायी पता सदन **न.** 175, सेक्टर 20-ए, चंडीगढ़ के रूप में दिया था। दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में बैंक *डिमांड* ड्राफ्ट संख्या 205322 और 205323 के माध्यम से भुगतान किया था। शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कागजात उसी डाक टिकट विक्रेता से 11 फरवरी, 1980 को सीरियल नंबर 3263 और 3264 के अंतर्गत खरीदे गए थे। दोनों ने डायरी न. 9968 और 9969 के माध्यम से एक ही दिन भुगतान किया। ये कारक याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई याचिका के खिलाफ स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं कि उनके संबंध तनावपूर्ण थे और वे अलग रह रहे थे या वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि पति-पत्नी द्वारा एक अलग आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था।

(16) एक अन्य तथ्य जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि यह जानने के बावजूद कि आवास बोर्ड आवंटन को रद्द करने के लिए आगे बढ़ रहा है, याचिकाकर्ता रविंदर कौर ने संपत्ति का कब्जा छोड़ दिया था और 7 लाख रुपये की राशि प्रतिवादी-हरजीत सिंह से स्वीकार कर ली थी। यह कार्रवाई याचिकाकर्ताओं को अच्छी रोशनी में नहीं दिखाती है। उनका प्रयास एक त्वरित पैसा कमाना और प्रतिवादी का एक निष्पन्न कार्य के साथ सामना करना था।

(17) इसका सामना करते हुए, श्री जैन का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं में से कम से कम एक को फ्लैट रखने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

(18) प्रामाणिक गलती के मामले *में,* एक गलत कथन को नजरअंदाज करना संभव हो सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने

झूठों की एक श्रृंखला बताई है। उन्होंने सच्चाई के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है। याचिकाकर्ताओं ने अपने द्वारा दिए गए गलत बयानों के लिए कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं दिखाया था। वास्तव में, यह दावा किया गया था कि उनके संबंध तनावपूर्ण थे। जब पत्नी ने फ्लैट के लिए आवेदन किया था तब वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। वे न केवल आवास बोर्ड को धोखा देने और गलत जानकारी देने की कोशिश करने के दोषी हैं, बल्कि उन्होंने प्रतिवादी-हैजीत सिंह को गुमराह करके काफी पैसा भी कमाया है। इस मामले की परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं को कोई भी राहत देना बेईमानी को बढ़ावा देने के बराबर होगा। हम ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए खुद को राजी नहीं कर सकते। वास्तव में, अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का उपयोग अन्याय को पूर्ववत करने के लिए किया जाना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। बेईमान और लालची को पुरस्कृत करने के लिए नहीं।

(19) श्री जैन का तर्क है कि यदि व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकरण को उनके द्वारा भुगतान की गई राशि को आंशिक रूप से जब्त करने की अनुमति देने के लिए राजी किया होता। हम इस तर्क को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई कुल राशि रु 24, 000 है। उन्होंने 18 साल से अधिक की अवधि के लिए परिसर पर कब्जा कर लिया है और अब एक फ्लैट प्रतिवादी-हरजीत सिंह को बेच दिया गया है जबकि दूसरा अभी भी उनके कब्जे में है। उन्होंने कई बार पैसे की वसूली कर ली है।

(20) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(21) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिन्हें परिणामस्वरूप खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति मेहताब एस. गिल के समक्ष, जे.

बचन सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य-उत्तरदाता

C.W.P. No. 8399 of 2000

24 मई, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-*दीवानी न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अवैध होने की सजा देने वाले आदेश को दरकिनार करते* हुए-*दीवानी न्यायालय के फैसले को अंतिमता प्राप्त हुई क्योंकि इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं*

की गई थी-अधिकारियों द्वारा समान आरोपों पर कारण दिखाओ नोटिस और आरोप पत्र जारी करना-प्रतिवादीगण की कार्रवाई अवैध है और नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा